: No. IRR 2-1/1.9/24/2022-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department (Computer No. 245 /1)0549/2023

/130549/2023

प्रेषक,

ई0 पत्रावली संख्या-24597

हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव

उत्तराखण्ड शासन्।

सेवा में.

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग-02 देहरादून : दिनांक 📑 फरवरी, 2023 जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में ल्वाली झील निर्माण की पुनरीक्षित विषय: लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3945 / प्र030 / सिं0वि० / नि०अनु०, दिनांक 08.11. 2021 एवं पत्र संख्या—3441 / प्र0अ0 / सिं0वि० / नि०अनु० / सी०एम०(योजना), दिनांक 27.09.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में ल्वाली झील निर्माण (घोषणा संख्या–259/2019) की पुनरीक्षित लागत रू० 1190.20 लाख (मूल लागत रू० 692.77 लाख + अतिरिक्त लागत रू० 497.43 लाख ) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त लागत रू0 497.43 लाख के सापेक्ष रू० 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि, योजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-740/11(2)-2019-03(31)/2018, दिनांक 28.06.2019 में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों तथा निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतू आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- प्रश्नगत प्रकरण में गठित जांच समिति की जांच रिपोर्ट / जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- प्रस्तावित जल संरचनाओं का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात योजना के लक्षित उद्देश्य (पेयजल एवं सिंचाई सुविधा) की पूर्ति के सम्बन्ध में नियोजन विभाग को अवगत कराया
- (iii) निर्माण कार्यों को Most Economic, Technically Feasible and Cost Effectiveness को ध्यान में रखते हुए सम्पादित कराये जाय।
- (iv) योजना से सम्बन्धित कार्यों की डिजाइन एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से अवश्य अनुमोदित करायी जाय।
- योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
- (vi) जल संरचनाओं का निर्माण कार्य इस प्रकार कराये जाय कि योजना के लक्षित उद्देश्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- (अं!) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (ना) निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, स्टोन, पी०बी०सी० पाईप cement, Steel एवं अन्य का i.S.Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।

(ix) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भट स्थानीय उपलब्ध सामग्री का है उपन जन

न्या होने ताली तज्ञतों से भी नियोजन को धरमत करामेंगे।

(x) कार्य निर्धारित अविध में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

(xi) निर्माण सामग्री यथा सीमेण्ट, स्टील एवं प्रयुक्त अन्य सामग्री का Frequency के अनुरूप से

N.A.B.L Laboratory से परीक्षण अवश्यक करा लिया जाय।

- (xii) आगणन का गढन अनुबन्धित दरों पर किया गया है तथा अतिरिक्त कार्यों हेतु एस0ओ0आर0 2021 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें है।
- (xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय।
- (xiv) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04. 2022 एवं शासनादेश संख्या-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 में अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय00—001—निदेशन तथा प्रशासन—05—निदयों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य की मानक मद—53—वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

अन्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमित के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक—Allotment ID.

Signed by Hari Chandra

भवदीय,

Semwal

Date: 17-02-2023 18:49:09

(हरिचन्द्र सेमवाल) सचिव।

## प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

1- महालेखाकार (ऑडिट) कौलागढ़, देहरादून।

2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।

3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।

5- राज्य योजना आयोग(नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।

6- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma Date: 20-02-2023 11:27:20

(जे०एल०शर्मा)